

R.N.I. 38784/81 डाक पंजीकरण सं B.S.T 59 बस्ती, वर्ष 45 अंक 314 शुक्रवार 7 जून 2024 (बस्ती संस्करण) बस्ती एवं अयोध्या-फैजाबाद से एक साथ प्रकाशित पृष्ठ 4मूल्य3.00 रुपया www.bhartiyabasti.com

एक नजर

बारिश और सेरवी थोड़ी राहत



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। मीषण गर्मी के बीच गुरुवार को मोर में बदले मौसम के निवाज ने लोगों को बड़ी राहत दी। मोर करीब चार बजे तक बादल छा गए। जोड़ा हवाएं प्रती और झोंकी ही देख बारिश शुरू हो गई। जिलेपर से कहीं कहीं धीरे तक मूसलाधार बारिश हुई तो कहीं हल्की बारिश ही हुई। इसके बाद सुबह करीब आठ बजे तक आसमानी में बने बादल छाप रहे से मौसम काफी सुहावा हो गया। इसके चलते तापमान का न्यूनता पार भी दो अंक तक लुप्त कर दी। सुबह दस बजे तक हल्की धूप निकल आई।
जिले के कुछ इलाकों में अंधी बारिश होने से खेतों में भी पानी जमा हुआ। इसके साथ ही शहर से लगावत ग्रामीण इलाकों में जलभराव की समस्या भी बन गई। कुछ जगहों पर लगावत पसर जाने से आवागमन भी बाधित हुआ। जोड़ हवा के चलते कुछ इलाकों में विद्युत आपूर्ति भी बाधित हो गई। लेकिन इन सबके बीच भीषण गर्मी से लड़ने पर परेशानी कम बरले मौसम से काफी सुख नजर आया। दिन में धूप निकलने के साथ ही तापमान का पार फिर से ऊपर चढ़ना शुरू हो गया।

अयोध्या की हार पचा नहीं पा रहे हैं लोग

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर उलटकर हुई है। लेकिन लोगों की आस्था से जुड़े अयोध्या की फैजाबाद सीट से भाजपा को मिली हार बड़ा का विषय बन गई है। बस्ती सीट की जीत-हार की समीक्षा के साथ ही लोग अयोध्या में भाजपा की हार को लेकर अपना-अपना नजरिया बसा कर रहे हैं। अधिकतर लोग यह कहते मिल जा रहे हैं कि अयोध्या की हार खल गई।
चाय, पान की गुप्तियों से लेकर समूह में बैठे लोगों की चर्चा का मुख्य केंद्र लोकसभा चुनाव परिणाम रहा। कुछ लोग तो यह कहते मिले कि सांसद से मले ही भाजपा हार गई, लेकिन अयोध्या से हारना ज्यादा खल रहा। केन्द्र व प्रदेश की सरकार ने अयोध्या के लिए न केवल राम मंदिर का निर्माण काया बहिक प्रया-प्रतिष्ठा कराकर आमजन को सौंप दिया।
कराड़ों रुपये का पैकेज देकर अयोध्या का विकास करवाये विषय पल्ल पर खड़ा किया। देव-विदेश से पर्यटकों को यहां आने के लिए एयरपोर्ट का निर्माण कराया। फिर भी राम नगरी से भाजपा प्रत्याशी का हार जाना समझ से परे है। पान की दुकान पर खड़े रामकाया उपाध्याय कहते हैं कि बस्ती की जनता ने बदलाव की बात को लेकर बोल दिया। चाय की दुकान पर बैठे रामसजीवन कहते हैं बस्ती का मुद्दल हो जाने से भी भाजपा को नुकसान पहुंचा।

गर्मी से जन, पशु हानि पर मिलेगी सहायता

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। वर्तमान समय में इसका 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने के कारण भीषण गर्मी, गर्म हवा, लू व तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। उच्च तापमान के खतरे हुए अगर जिलाधिकारी बि./रा. कमलेश चन्द्र ने बताया है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलमी क्षेत्रों में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान को अधिक माना जाएगा।
उन्होंने जनपद के समस्त तहसीलों के उपनिष्ठाधिकारी को निर्देशित किया है कि उनके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कि जिले उपाधिकारी प्रशासिक हेतु बस्ती के कारण हो रही है, तो उप दस घंटे में मृतक का पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट कराये जाये, जिससे कि मृत्यु के कारण की भीष्ट हो सके और प्रमाति ध्यात की मृत्यु हीटवेब से होना प्रदर्शित होता है, तो आपदा मंत्रालय निदेशावली के अनुसार तकमाल अतिरिक्त सहायता दिया जाना सुनिश्चित करें

गठबंधन सरकार गठन से पहले उठी अग्निवीर योजना में बदलाव की मांग



नई दिल्ली (आभा)। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। इसके चलते नरेंद्र मोदी को अब नौतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टियों के समर्थन से सरकार चलानी पड़ेगी। अब तक सरकार गठन को लेकर कोई रुफखा तय नहीं हुई है, लेकिन नौतीश कुमार की पार्टी ने पहले ही तीर चल दिया है। जेडीयू के प्रस्ताव केसी त्यागी ने गुरुवार को सेना में जवानों की सर्ती के लिए एक अग्निवीर योजना में बदलाव की मांग कर दी। उन्होंने कहा, 'अग्निवीर स्कीम का बहुत विरोध है। हुआ था और चुनाव में भी इसका अस्तर देखा ने को मिला था। इसलिए अग्निवीर स्कीम पर दोबारा सोचने की जरूरत है।'
केसी त्यागी ने 'आज तक' से बातचीत में कहा कि यह स्कीम जब आया था, तब लोगों ने काफी विरोध किया था। सेना में तैनात लोगों के

कुर्मी महासभा ने सांसद चुने जाने पर राम प्रसाद चौधरी को दिया बधाई



—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। कुशवार को भारतीय कुर्मी महासभा के अध्यक्ष डा. बी०के० सी० प्रसाद पदाधिकारियों और सदस्यों ने बस्ती लोकसभा से नव निर्वाचित सांसद राम प्रसाद चौधरी से उनके निजि आवास पर मुलाकात कर मंडू देकर जीती की प्रशन्नता व्यक्त किया।
सांसद राम प्रसाद चौधरी ने भारतीय कुर्मी महासभा पदाधिकारियों

शेयर बाजार के सबसे बड़े घोटाले में मोदी, शाह शामिल -राहुल गांधी



नई दिल्ली (आभा)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बताया किया है कि शेयर बाजार पर सरकार की ओर से की गई टिप्पणी से लाखों खुदरा निवेशकों का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि इससे निवेशकों को 30 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि यह शेयर बाजार का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। इसकी संसदीय समिति से जांच कराई जानी चाहिए। राहुल ने कहा, हमने मोदी किया कि चुनाव के समय प्रशासन ने, गृह मंत्री और वित्त मंत्री ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टॉक मार्केट तो जैसे से आगे बढ़ने जा रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए कहा।
अमित शाह कहते हैं कि 4 जून से पहले शेयर खरीदे। मोदी खरीदे हैं कि यह चार नौ को स्टॉक खरीदे।
1 जून को मीडिया बूट एरिजेंट पल निकालती है। भाजपा को जो अतिरिक्त एरिजेंट पल था, उसमें उसे 220 सीटें मिल रही थीं। 220 से 230 सीटों के मिलने के बारे में बताया था। स्टॉक मार्केट तीन जून को सारे रिटर्न टॉड देता है और 4 जून को घडाम

है। खबर है कि नरेंद्र मोदी 8 या फिर 9 जून को पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। सरकार गठन को लेकर दिल्ली में भाजपा को शीघ्र नेताओं की मीटिंग भी चल रही है।
जबकि दूसरी ओर तेलुगु देशम पार्टी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में गुरुवार को विजयवाड़ा में पार्टी के नवनिर्वाचित

संसद परिसर के भीतर गांधी, अंबेडकर, छत्रपति शिवाजी की मूर्तियों को मूल स्थान नई दिल्ली (आभा)।

संसद परिसर के भीतर महात्मा गांधी, बी आर अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी सहित अन्य की मूर्तियों को दूंसफर किए जाने को लेकर बवाल मचा है। इस कदम को लेकर कांग्रेस ने तीथी आलोचना की। आदिवासी नेता विरसा मुंडा और महाराणा प्रताप की मूर्तियों को भी पुराने संसद भवन और संसद पुस्तकालय के बीच एक लॉन में दूंसफर कर दिया गया है। मुनिमॉन के दौरान मूर्तियों को दूंसफर किए गए पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रेग्हा ने एक्स पर कहा, 'छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी और डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर की मूर्तियों को संसद भवन के सामने उनके प्रमुख स्थानों से हटा दिया गया है। यह अत्याचारपूर्ण है।'
कांग्रेस के मीडिया और प्रचार

विवाह का झांसा देकर दुष्कर्मी पीड़िता ने लगाया न्याय की गुहार

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। लालाजगन्ना क्षेत्र के एक मांग से विवाह का झांसा देकर प्रेम करने और बाद में विवाह से इंकार और श्रीमि द्वारा शिकायत करने पर जान से मार देने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर कहा है कि लालाजगन्ना क्षेत्र के सिपाई बाबू निरासी प्रदीप चौधरी पुत्र शेराम चौधरी ने वर्ष 2022 में उसे लिपट देकर बस्ती पहुंचाया और फोन नम्बर ले लिया। उसके बाद दोनों ने बातचीत होती रही। 1 फरवरी 2024 को प्रदीप चौधरी ने उसे कोपे गये के बंधे पर बुलाया और नशीली दवां सुयांकर बस्ती एक हॉटल में लाकर डरा धमकाकर गलत काम किया। प्रदीप

एक आपराधिक कार्य था।

रायबरेली व बायाना से विजयी सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, 'पहली बार हमने यह मोदी नौ किया कि चुनाव के समय प्रशासनी, गृह मंत्री, वित्त मंत्री ने शेयर बाजार पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने दो-चार बार कहा कि शेयर बाजार तेजी से बढ़ने जा है। उनके मैसेज को वित्त मंत्री और गृह मंत्री ने भी आगे बढ़ाया। अमित शाह कहते हैं 4 जून से पहले शेयर खरीदो। प्रधानमंत्री ने भी वही कहा और 28 मई को फिर से दोहराया। 3 जून को शेयर बाजार सारे रिटर्न टॉड देता है और 4 जून को शेयर बाजार नीचे चल जाता है 18 करोड़ से नेता राहुल गांधी ने कहा, भाजपा के सबसे बड़े नेताओं ने रिटेल इंडस्ट्री को मैसेज दिया है... उनके पास जानकारी है कि भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने वाला है, वे जानते थे की 3-4 जून को क्या होगा और क्या... 30 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और हजारों-लाखों करोड़ रुपया का नुक हो चुका है। इसके साथ ही उन्हें समझनी, गृह मंत्री, जिन्होंने एरिजेंट पोल किया उनपर और नशीली निवेशकों पर जांच चाहते हैं।'
आदेश दिया? दोनों को इंटरव्यू किए गए। ये अजायब की ही शैली को दिए गए। उन पर पहले ही शैली की जांच बेटी है तो उस पर जांच होनी चाहिए। मोदीजी के जो फोन इंक्वैरी हैं और जो विदेशी निवेशकों हैं। इनके बीच क्या रिश्ता है और अगर रिश्ता है तो इसकी जांच होनी चाहिए। इसके लेखक हमारे पत्र सवाल हैं। हम सड़ घोटाले को लेकर जेडीपी की मांग करते हैं। इस पूरे मामले में निवेशकों ने करोड़ों पाना है। यह

वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सीएम योगी ने किया समीक्षा: दिये निर्देश

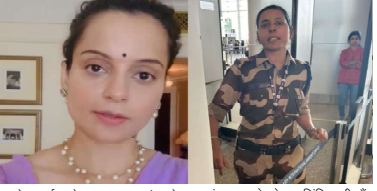
लखनऊ (आभा)। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष समेत दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली चुनाव में हुईं। हालांकि दिल्ली जाने से पहले सीएम योगी एक्सप्रेस फौज में नजर आए। सीएम योगी ने तुरंत प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को मीटिंग के लिए बुला लिया। सीएम योगी ने अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक कर लॉकडौन से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। सीएम सरकार के एक प्रस्ताव में यहां बताया कि इस उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति और भावी कार्ययोजनाओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इस दौरान सीएम योगी विकास कार्यों की जानकारी ली। सीएम योगी ने इस दौरान बरसात से निपटने की व्यवस्थाओं को भी जाना। मीटिंग में सीएम योगी ने बाबू, मौरंग, मिट्टी से संबंधित भी अफसरों को जरूरी निर्देश जारी किए।



मुख्यमंत्री ने सीएम योगी के मनेद्वारा पूरे प्रदेश में कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती नहीं करने की हिदायत देते हुए कहा कि ट्रांसफार्मर जलने, तार गिरने और 'ड्रिपिंग' जैसी समस्याओं का तुरंत निराकरण किया जाए। मीटिंग में सीएम योगी ने बरसात से निपटने के लिए अफसरों से ज्ञान बताने को कहा। साथ ही नालों की सफाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मिलन बस्तियों में साफ-सफाई की अत्यधिक आवश्यकता है। 'नियमित 'फॉगिंग' करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, बरसात के मौसम में संचारी रोगों के प्रसार की सजाहिक आशंका होती है, इसके महेनजर समय से पूरी तैयारी कर लें। चिकित्सकों के साथ-साथ आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी पूरा सहयोग दें। लोगों में जागरूकता बढ़ाने के भी प्रयास हों। आदिवासी व बाबू, मौरंग और मिट्टी जैसे उपखण्डों का कृत्रिम अभाव पैदा करने वाले कालाबाजियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के

महिला सीआईएसएफ कर्मी ने कंगना रौत को जड़ दिया थप्पड़

वडीपड (आभा)। चंडीपड एयरपोर्ट पर बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रौत को एक महिला सीआईएसएफ कर्मी ने थप्पड़ मार दिया। महिला कंगना रौत के किसान आंदोलन के समर्थन में आवाज देने से आज्ञा थी। उन्होंने बताया कि उनकी मां की मिला आंदोलन के दौरान विरोध प्रदर्शन के लिए बैठती थीं। कंगना रौत को थप्पड़ मारने के बाद 800 कर्मी कुलविरत करने के बाद, शर-होने बयान दिया था कि किसान 100 रुपये के लिए वहां बैठे हैं। क्या वह वहां जाकर बैठेंगे? मेरे मां वहां बैठी थीं और विरोध कर रही थीं जब उन्होंने यह बयान दिया। वहीं, कंगना रौत को थप्पड़ मारने के बाद कुलविरत कोर को संरक्षक कर दिया गया है। एक सीनियर सीआईएसएफ अधिकारी ने मामले पर बात करते हुए कहा कि महिला कॉन्स्टेबल के खिलाफ स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत करते हुए एफआईआर दर्ज करावाई गई है। इसके साथ ही उन्हें समझनी भी कर दिया गया है। चंडीपड एयरपोर्ट पर कंगना के विमान में सवार होने से



पहले हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान सीआईएसएफ कर्मी ने एक्ट्रेस को थप्पड़ मारा। कंगना ने एक वीडियो बयान जारी कर कहा कि दिल्ली जाते वक्त चंडीपड हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान सीआईएसएफ कर्मी एक महिला सिपाही ने उन्हें थप्पड़ मारा और उसके साथ गांधी-पतौली की। कंगना ने पंजाब में आतंक और हिंसा में हेलन करती वीडियो शीर्षक के साथ कंगना रौत को थप्पड़ मारने के लिए निर्दिष्ट किया। बीजेपी सांसद कंगना रौत ने वीडियो में कहा कि वह सुरक्षा और डीक है, लेकिन पंजाब में बढ़ते

शिक्षक, शिक्षा मित्रों के वेतन, मानदेय बहाली के लिये सौंपा ज्ञापन

—भारतीय बस्ती संवाददाता—
बस्ती। गुरुवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष चन्द्रिका सिंह के नेतृत्व में संघ पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधि मण्डल ने जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। मांग किया कि चुनाव खिपुटी के दौरान विषम परिस्थितियों में अनुपस्थित रहने वाले 96 शिक्षक और शिक्षा मित्रों के वेतन और मानदेय को बहाल किया जाए। इसी क्रम में सोनाहा थाना क्षेत्र के खेरा टोल म्यूनिस्पाल निवासी सहायक अध्यापक सुदीप कुमार उपाध्याय जिम्मेदार इन्ट्रैज्जु जमा करते समय तबियत बिगड़ने से मौत हो गई थी उनके परिजनों के माता द्वारा पिछले निरस्त देयकों को भुगतान कराया जाना। मुख्य विकास अधिकारी ने शिक्षकों के प्रतिनिधि मण्डल को आश्वासन दिया कि शिक्षक आर्थिक मित्रों के वेतन और मानदेय को

पत्नी को एक लाख 10 हजार रुपये की राशि उपलब्ध कराया गया है। दुःखी परिवार को जय तक समस्त सुविधा नहीं मिल जाती संघ निरन्तर साक्ष्य रहेगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान मुख्य रूप से जिला उपाध्यक्ष प्रवीण श्रीवास्तव, सुधीर तिवारी, के साथ ही संजय यादव, सुरेश गौड़, मुल्लेश्वर, अखिलेश पाण्डेय, आशीष पट्टे, अपरिषि, सनन प्रद, सन्तोष पाण्डेय, विवेक प्रसाद सिंह के साथ ही संघ के अर्क पदाधिकारी, शिक्षक शामिल रहे।



"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्स

भारतीय बस्ती

बस्ती 7 जून 2024 शुक्रवार

सम्पादकीय

गठबंधन की डगर पर देश

केन्द्र में बैशाखी एनडीए गठबंधन या डील की सरकार को चलाना मोदी जैसे ब्यक्तिवत् के लिये आसान नहीं है। शपथ ग्रहण के पूर्व ही निरयुक्त तो पर नीतीश कुमार और चन्द्रबाबू नायडू मंत्रिमण्डल में महत्वपूर्ण विभाग भी मांगे ही, ऐसे में यह सरकारी कब तक और कितना चल पायेगी इसके लिये तो इन्तजार करना होगा किन्तु मतदाताओं में जिस प्रकार से उलझाया है ऐसे में मोदी की तीसरी पारी को मजिल तक पहुँचा पाना आसान नहीं है। फिलवक्त अभी इंतजार करना होगा किन्तु लक्षण अभी से दिखने लगे हैं।

लोकसभा चुनाव का शोर-शराबा खत्म हो गया है और अगले कुछ दिनों में नई सरकार आने वाली है, अब हर किसी के लिए स्पष्ट होने का समय आ गया है। रिफॉर्ड डेड महीने तक चले व्यस्त चुनाव अभियान के दौरान उत्पन्न कड़वाहट को अब परास्परिक रूप से समानजनक और सकारात्मक भावनाओं का रास्ता देना चाहिए और हर किसी को राष्ट्र निर्माण के कार्य में लग जाना चाहिए। उम्मीद है कि हिंदू-मुस्लिम कार्ड, जिसने चुनाव अभियान को प्रभावित किया, हमेशा के लिए दफन हो जाएगा और हम एक विकसित भारत की दिशा में काम करेंगे। सरकार और विपक्ष को अब एक-दूसरे के प्रति उचित सम्मान और आदर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। नई सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह सकारात्मक शुरूआत करे और चुनाव प्रचार के दौरान लगाए गए आरोपों या कहे गए कठोर शब्दों के लिए 'हिस्सा बराबर' करने के लिए राजनीतिक प्रतिशोध में शामिल न हो।

दांच बहुत उच्च थे और इसलिए नेताओं ने तथ्यों की पुष्टि किए बिना या राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के शब्दों को तोड़-मरोड़कर पेश किए बिना ही एक-दूसरे के खिलाफ कदम बढ़ा दिए और एक-दूसरे पर आरोप लगाए। नई सरकार ने अपने लिए काफी निर्धारित कर लिया है। हालांकि राष्ट्र ने प्रगति की है, विशेषकर बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में। इसे अभी भी कुछ गंभीर समस्याओं से जुझना बाकी है। इसकी शुरुआत अच्छी खबर के साथ हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2024 के लिए सकल घरेलू उत्पाद को इस साल फरवरी में जारी 7.6 प्रतिशत के दूसरे अग्रिम अनुमान से बढ़ाकर 8.2 प्रतिशत कर दिया गया है।

इस बीच, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन.एस.ओ.) द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, वास्तविक सकल मूल्यवर्धित (जी.पी.ए.) बढ़ वित्त वर्ष 2024 में 7.2 प्रतिशत हो गया जो 2022-23 में 6.7 प्रतिशत था। कृषि क्षेत्र के खराब प्रदर्शन के बावजूद सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) ने प्रभावशाली 8.2 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की, जो दशकीय औसत 4.4 प्रतिशत से काफी नीचे 1.4 प्रतिशत की दर से बढ़ी। हालांकि नई व्यवस्था के लिए असली चुनौती विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर उपाय करके विकास के स्तर को बनाए रखना होगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आर्थिक विकास का लाभ व्यापक रूप से सबको मिले।

लेकिन सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रोजगार पैदा करना और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना है। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी (सी.एन.आई.) की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बेरोजगारी दर मार्च 2024 में 7.4 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल 2024 में 8.1 प्रतिशत हो गई। शहरी भारत के साथ-साथ ग्रामीण भारत में भी बेरोजगारी दर तेजी से बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का तनाव मनरेगा नौकरियों की भारी मांग में परिलक्षित होता है।

भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक वसु ने कहा है कि सी.एन.आई.ई. डाटा से पता चलता है कि युवा बेरोजगारी दर 45.4 प्रतिशत के खतरनाक स्तर तक पहुँच गई है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इससे गहरा नुकसान हो रहा है। देश की खातिर हमें नारों के पीछे नहीं छिपना चाहिए बल्कि राजनीति को किनारे रख सुधारवादी कदम उठाने चाहिए।

हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने बताया है कि 45.4 प्रतिशत का यह आंकड़ा 20 से 24 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं से संबंधित है। लेकिन तथ्य यह है कि पिछले 10 वर्षों में बेरोजगारी वास्तव में बढ़ी है और लगभग कोई नई नौकरियाँ पैदा नहीं हुई हैं। युवा बेचोरा हो रहे हैं और झपटमारी, डकैती और चोरी जैसे अपराधों में वृद्धि हो रही है। नई सरकार को मध्यम और लघु उद्यमों को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो 10 मिलियन से अधिक नौकरियाँ प्रदान करते हैं और जिन्हें नोटबंदी, जी.एस.टी. की शुरूआत और अंततः कोविड महामारी के कारण भारी झटका लगा है। प्रत्यक्ष दक्षता का दूसरा क्षेत्र कृषि क्षेत्र है। इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है और कृषि को आधुनिक बनाने तथा सब्सिडियों, अनाजों और फलों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

जलवायु परिवर्तन और विजली की कमी एक अन्य क्षेत्र है जिसके लिए सकारात्मक सरकारी नीतियों की आवश्यकता है। वर्तमान गर्मी की लहर और विजली की मांग में तेज वृद्धि मध्यम की जरूरतों को संकेत है। अंतिम लेखन महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को स्कूलों और उच्च शिक्षा, और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं दोनों स्तरों पर शिक्षा के मानकों में सुधार पर ध्यान देना चाहिए। देश अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए नई सरकार की ओर देखा रहा है।

बीजेपी के हिन्दुत्व पर भारी पड़ी सपा, कांग्रेस



—अनुज कुमार—

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यूपी में खराब परफार्मेंस की वजह से बीजेपी केन्द्र में अपने दम पर बहुमत का भी आकड़ा नहीं पा कर पाई। भले ही एनडीए के तौर पर उसकी सरकार बनना तय लग है, लेकिन अबकी से उसके सामने चुनौती बड़ी होगी। बीजेपी का यह सारा खेल यूपी ने बिगाड़ा है। 2017 के विधान सभा चुनाव के बाद जिस तरह से अल्पसंख्यक तरीके से बीजेपी अलकमान द्वारा योगी को यूपी का सीएम बनाया गया था, उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के विधान सभा चुनाव के बाद जिस तरह से साथ योगी का भी रिस्का खूब चला। यहां फंडे की भी चुनाव घोषित मोदी आगे तो योगी उनके पीछे नजर आते थे। अपने बल पर शानदार प्रदर्शन करने वाले सीएम योगी आदिवासीयों का जादू अबकी लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं चला यह यह प्रश्न है। कहा यह भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक (पीडीए) फार्मूला ने बीजेपी के हिन्दुत्व को हलिये पर धकेल दिया। जबकि जमीनी हकीकत यह है कि यूपी की सिपायरी लोकसभा भले योगी मान खग गये हों, लेकिन उनकी सरकार के कामकाज को लेकर किसी को कोई खास नाराजगी नहीं। आज भी प्रदेश में नई एंड आउट के कारण उनकी छवि काफी बुरी दिखती है। विकास के कार्य भी दीकारक चल रहे थे, ऐसे में यही कहा जा सकता है कि शायद योगी



अपनी बात को मतदाताओं के सामने उठाने सही तरीके से नहीं जैसा कि सपा मुख अखिलेश यादव करने में सफल रहे। वहीं बसपा के चोटर को भी जब इस बात का अहसास हुआ कि वहनजी अबकी से रसे में नहीं है तो उसने भाजपा की जगह समाजवादी पार्टी का साथ ज्वाप प्रदान किया, यह भी बीजेपी के लिये माइंस प्लस टर्न रहा। इसकी वजह भी साफ है। दलित और उससे साथ पिछड़ा वर्ग को भी इस बात का विश्वास हो गया था कि यदि मोदी मजबूत हुए तो उनका आरक्षण खत्म हो जायेगा।

बहरहाल, योगी की भविष्य की राजीव पर लोकसभा चुनाव के नतीजे का प्रभाव पड़ना निश्चित है। एक तरह विश्वास उनके खिलाफ ज्वादा हमलावर होगा तो पार्टी के भीतर से भी उनके खिलाफ आवाज उठने लगेगी। क्योंकि अक्सर ऐसी खबरें आती थीं कि योगी राज में बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को कोई महत्व नहीं मिल रहा था और इसकी बड़ी वजह योगी को समझा जा रहा था। यहाँ तक की चौकी-थाने तक भी बीजेपी नेताओं और पार्टी की बात तो पूरे विधायकों और सांसदों तक की नहीं सुनी जाती थी। यूपी में भाजपा के साथ-साथ उसके सहयोगी दलों को भी झटका लगाता है।

सुभासपा के बढ़ बोलते नेता ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता पाये तो संजय निपाद की पार्टी का भी एक सीट पर खता नहीं खुला। हाँ, राष्ट्रीय लोकदल अपनी दो और अपना दल एस की अनुग्रिया पटेल मिर्जापुर से चुनाव जीत गई हैं। वहीं, सुभासपा को घेरी लोकसभा सीट पर झटका लगा है। इंडिया गठबंधन प्रदेश की 80 में से 43 सीटें जीतने में सफल रहा। इन्होंने सपा की 37 सीटों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। कांग्रेस को भी 6 सीटों पर जीत हासिल हुई, लेकिन इसका श्रेय भी अखिलेश को ही दिया जा रहा है। वहीं, भाजपा के नेतृत्व में एनडीए 36 सीटों पर जीत हासिल कर पाई जिसमें भाजपा की 33 सीटें थीं। यूपी में उसके सात केन्द्रीय मंत्री चुनाव हार गये। एक सीट पर आजाद समाज पार्टी को जीत हासिल हुई।

दस वर्षों में बाद अबकी से यूपी के वॉटिंग पेटन में बड़ा बदलाव को मिला। भाजपा बड़े स्तर पर पिछड़ी, यह तो खबरे देखा, पल्लु यूपी पिछड़ी इसको लेकर उसके अंदर भी बुकिना शुरू हो गई है। जो बीजेपी 2019 में यूपी में 63 सीटें जीती थीं जो अबकी से बडे 33 पर रिमिट गई। पार्टी को 30 से सीटों का नुकसान पड़ना पड़ा। वहीं, कांग्रेस का आकड़ा एक से छह पर

पहुँच गया है। 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार कांग्रेस ने चुनाव में बहत बनाई है। वहीं, समाजवादी पार्टी अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रही है। 1992 में समाजवादी पार्टी के गठन के बाद से अब तक का यह उसका सबसे शानदार प्रदर्शन था। इतना बेहतर प्रदर्शन तो किसी भी लोकसभा चुनाव में स्वयं मुलाम सिंह यादव तक नहीं कर पाये थे। इससे पूर्व 2004 में सपा ने 35 सीटें जीती थीं। इससे यही लगता है कि इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति बेहतर तरीके से जमीन पर उतरने में सफल रही है, भाजपा के पक्ष में माहौल बनता नहीं दिख पाया। ऐसे में यूपीया प्रदेश नेतृत्व में बलवा की रणनीति पर काम कर सकता है। इस पर चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन यह चर्चा हवा-हवाई ज्वादा लगती है।

यह वह चर्चा है जिसे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले हवा दी थी। उन्होंने दावा किया था कि लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में सत्ता परिवर्तन होगा। योगी आदिवासीय मुखमंत्रि पद से हटाए जायेंगे। लखनऊ में इंडिया गठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने सीएम योगी आदिवासीय पर बड़ा दावा किया

था। केजरीवाल ने कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदिवासीय दिल्ली आए थे। उन्होंने मुझे गालियां दीं। योगी जी, मैं आपसे विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि आपके असली दुश्मन आपकी ही पार्टी में हैं। भाजपा में अपने दुश्मनों से लड़िए। आप केजरीवाल को गाली क्यों दे रहे हैं? अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह आपको हटाना चाहते हैं। आपको यूपी के सीएम की कुर्सी से हटाने की पूरी तैयारी चल रही है। आप उनसे निपटिए। केजरीवाल ने लोगों से कहा था कि इंडिया को बचाना है तो इंडिया गठबंधन को जीतना है।

अमलीतर पर बीएसपी को विपक्ष भाजपा की ही टीम कहकर टारगेट करता रहा है पर कहानी कुछ और ही चल रही है। परिधम से पूर्व तक मायावती ने ऐसे कैंडिडेट खड़े किए जो एनडीए कैंडिडेट्स को भी नुकसान पहुँचा रहे थे। परिधम की ही मंशेर में देवदास त्यागी, मुसुमकरनारायण दारा सिंह प्रजापति, खीरी सीट से बीएसपी का पंचांगी प्रत्याशी आदि बीजेपी को सीधे नुकसान पहुँचा रहे थे। इसी तरह मुंबई यूपी में घोसी में बीएसपी ने जो कैंडिडेट दिया। वह सीधा इमरालद कि पार्टी ने एनडीए का काम खराब करने का ठेका ले लिया है। घोसी सीट पर बालकृष्ण बोहान ने एनडीए की 2 साल पुरानी तेसरी को ही पतली बना दिया। यहां पर बीजेपी ने नौमीय नौमीय नेता दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी से हारिहरी ही लाए गए थे कि उनका नाम घोसी आए और आपस की सीटों पर लिया जा सके, पर जब बीजेपी ने एक नौमीय जालि के कैंडिडेट बालकृष्ण बोहान का खड़ा कर दिया तो जाहिर के बेचने के आरोप भी लगे। मगर इसके बावजूद बसपा के कोर वोट बैंक को कोई खास अरन नहीं पड़ा। फिलहाल इस बार के नतीजों से कुछ अलग ही हालात सामने आ रहे हैं। इस बार मायावती का वोट बैंक उसके साथ नहीं रहा है। इस बार दलित वर्ग के पूरे-रिखे बीजेपी का एक साथ तबका इस बात से नुरी तरह सहमत है कि बीजेपी को हारने के लिए बसपा को विश्वी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए था, जब एसा

नहीं हुआ तो उम्मीद लोगों ने इंडिया गठबंधन के एनडीए के समर्थन में वोट देने का फैसला किया, इससे उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों को ऐसी सफलता मिली है, जिसकी उम्मीद उम्मीद भी नहीं थी। इस तरह देखा जाए तो मायावती की राजनीतिक कूकड़ फिलहाल अपने कोर वोट बैंक पर कमजोर होती दिख रही है।

वोटकटवा बनकर रह गई बसपा

—नीरज कुमार दुबे—

बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती एक समय उत्तर प्रदेश और की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाती थीं लेकिन समय ने ऐसी कवच बदली कि आज बसपा सिर्फ वोट कटवा पार्टी बन कर रह गयी है। अपनी शर्तों पर राजनीति करती रही मायावती की पार्टी का उत्तर प्रदेश में मात्र एक विधायक है जबकि कभी यहां उनके पास पूर्ण बहुमत हुआ करता था। मायावती ने चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री का पद संभाला लेकिन आज वह अपने पार्टी को नहीं संभाल पा रही हैं। चुनाव विधानसभा के हो या लोकसभा के, मायावती और बसपा जिस भेन से चुनाव लड़ते हैं उससे आरोप लगाते हैं कि वह भाजपा की ही टीम हैं। जब अब दलों की तीन-चार दर्जन रैलियां हो जाती हैं तब मायावती प्रचार के लिए निकलती हैं।



अब जबकि लोकसभा चुनाव परिणाम सामने आ गये हैं तो एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि मायावती की ओर से अकेले लड़ने का निर्णय संभव: भाजपा की मदद करने के लिए किया गया था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भले एक भी लोकसभा सीट नहीं जीती हो लेकिन उसने 16 सीटों पर दूसरों का खेल बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। 16 सीटों पर बसपा को जितने वोट मिले हैं वो मुख्य प्रतिद्वंद्वियों की हार और जीत के अंतर से ज्यादा है। यह सभी 16 सीटें एनडीए के खाते में गयी हैं।

गलत था लेकिन चुनावी रैलियों के दौरान विभिन्न दलों के नेता आकाश आनंद से भी ज्यादा बड़-बड़कर बातें कर रहे थे। अब जबकि लोकसभा चुनाव परिणाम सामने आ गये हैं तो एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि मायावती की ओर से अकेले लड़ने का निर्णय संभव: भाजपा की मदद करने के लिए किया गया था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में भले एक भी लोकसभा सीट नहीं जीती हो लेकिन उसने 16 सीटों पर दूसरों का खेल बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। 16 सीटों पर बसपा को जितने वोट मिले हैं वो मुख्य प्रतिद्वंद्वियों की हार और जीत के अंतर से ज्यादा है। यह सभी 16 सीटें एनडीए के खाते में गयी हैं। इनमें से 14 सीटें भाजपा के पास हैं। एक सीट राष्ट्रीय लोक दल के पास और एक सीट अपना दल (सोनेलाल) के पास गयी है। कल्पना कीजिये कि यदि मायावती के उम्मीदवारों मेंदान में नहीं होते तो भाजपा को 240 की जगह 226 सीटें ही मिली होती और एनडीए का कुल आंकड़ा

भी 278 सीटों का ही होता। आज उत्तर प्रदेश में भाजपा जो 33 सीटें जीतकर आई है यदि मायावती के उम्मीदवार नहीं होते तो यह नंबर 19 हो सकता था। मायावती ने भाजपा की किस तरह मदद की इसको कम करने के लिए उत्तर प्रदेश की भदोही सीट को देखें जहां पर बसपा प्रत्याशी की 1.6 लाख वोट मिले जिसने भाजपा उम्मीदवार डॉ. विनय कुमार बिंद की जीत का रास्ता साफ कर दिया। इसी प्रकार मिर्जापुर में अपना दल (सोनेलाल) की अनुग्रिया पटेल 378/10 वोटों से जीत पाई क्योंकि बसपा के नमिष कुमार ने 1.4 लाख वोट लेकर सपा उम्मीदवार का खेल बिगाड़ दिया। मायावती के कारण इंडिया गठबंधन के खाते में अपना से जीत रहे गयीं उनमें अकबरपुर, अलीगढ़, अमरगढ़, बांसगांव, भदोही, बिजनौर, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर सीकरी, हरदोई, मेरठ, मिर्जापुर, मिर्जापुर, फूलपुर, शहजहांपुर और उन्नाव सीटें शामिल हैं। हम आइये की यह दावा दिता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान भी निचले स्तर तक यह संदेश पहुँचा था कि मायावती ने

अपने वोट बैंक को भाजपा की मदद करने के लिए एक किया है। हालांकि इस संदेश की सत्यता प्रमाणित नहीं हो पायी थी लेकिन इसने भाजपा को भारी लाभ पहुँचाया था।

यह चुनाव परिणाम दर्शाते हैं कि बसपा का कोर वोट बैंक दलित और जाटव अब इंडिया गठबंधन के खाते में आ रहा है। बसपा के वोट बैंक में तीन पीसदी की गिरावट इस बात की जरूरत पर जोर देते हैं कि पार्टी नेतृत्व को अब गंभीरता से अपने भविष्य पर विचार करना चाहिए। पिछले लोकसभा चुनावों में मिली 10 सीटों की बराबर बसपा का इस बार शून्य पर सिमटना, ज्यादातर बसपा उम्मीदवारों की जमानत जब्त होना और बसपा की सोशल इंडीविजुअलिटी फोर्नुनी की हवा निकलने से मायावती का भड़कना भी स्वभाविक है।

मायावती को थूँटि इस बार मुस्लिमों का वोट विलुक्त नहीं मिला है इसलिए उनका आहत होना भी स्वाभाविक है लेकिन उनका सार्वजनिक रूप से किसी कोम को यह कहना गलत है कि वोट नहीं देने वालों को हम भविष्य में सोच समझ कर मौका देंगे। मायावती का यह बयान यह भी दर्शाता है कि वह भी उन नेताओं में शामिल हैं जो टुट्टिकरण की राजनीति करते हैं। देखा जाये तो टुट्टिकरण की राजनीति के लाभ अलकातिक ही होते हैं जिसने भी इसे अपनी राजनीति का आधार बनाया है उसकी जमानत एक ना एक दिन खिसकी ही है।

हिन्दी पट्टी में कांग्रेस का उत्थान



—के.एस. तोमर—

2024 का संसदीय चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए बरदान साबित हुआ है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के लिए अपने राजस्थान, हरियाणा आदि में पुनरुत्थान के एक नए युग की शुरुआत करता है, जिसका श्रेय भाजपा के प्रचार अभियान की विभाजनकारी प्रकृति और हिंदुत्व पर ध्यान केंद्रित करने को दिया जा रहा है। किसानों, ग्रामीण संकट, आम लोगों की परेशानियाँ, बेरोजगार युवाओं की समस्या, आत्ममान घूँटी कोमर्त आदि की अनदेखी की जाती रही है। पंजाब और पश्चिम बंगाल में अनेक चुनाव लड़ने के कांग्रेस पार्टी के फैसले का उसे भरपूर लाभ मिला क्योंकि आम आदमी पार्टी और पूंजूमूल कांग्रेस ने सीधे तौर पर भंगवा वोटों के प्रभावित किया। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जीतीं और इसका पुनरुत्थान पार्टी कार्यकर्ताओं को फिर से जीवंत कर देता, जो सप्ते प्रदर्शन में अनेक प्रदर्शन में लगातार गिरावट देख रहे हैं। अखिलेश यादव यूपी में गठबन्धन के पूरे गेम प्लान के सुपर हीरो हैं क्योंकि उन्होंने गैर यादव उम्मीदवारों को प्राथमिकता देकर भगवत करते हुए सोशल इंडीविजुअलिटी को और 5 टिकट दलितों को और 5 टिकट उन्नाव यादवों को आबंटित किए।

'करिसे' पर आलाकमान का अति-विश्वास वास्तव परिणाम देने में विफल रहा। मोदी को गठबंधन सहयोगियों को एकजुट करने के लिए अपने राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा क्योंकि दलगत बड़ा नाम बू के नेतृत्व वाली लेटरू देशम धीरू (दिवांग) की बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किंग मेकर के रूप में उभरें हैं भाजपा से सत्ता जित सकेंगे। दूसरा, भाजपा ने अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान कभी भी अपने सहयोगियों को महत्व नहीं दिया और यहाँ तक कि चुनाव भी मोदी ब्रांड की गारंटी पर कैंडिडेट रहा।

अब नव-निर्वाचित सांसदों के शायद लेने के बाद संसद में उदरार अलग होगा क्योंकि भाजपा की चिल्लाने वाली ब्रिगेड का मुकाबला करने के लिए 'इंडिया गठबंधन' को सत्ता 234 की मजबूत ताकत होगी। राणगा को 10 वर्षों के दौरान प्रचंड बहुमत के साथ बेहलावा था। सत्ताचूद दल को लोकसभा को चुनकर रुत से चलाने के लिए एक रणनीति बनानी होगी, जिसकी आवश्यकता तब नहीं थी जब भाजपा और उसके सहयोगी दलों का शासन था। तीसरा, पिछले न 'अनिश्चित' योजना का भरपूर फायदा उठाया, जिसकी समीक्षा की आवश्यकता हो सकती है, खासकर तब जब कई संवैधानिक जनताओं ने सेना में अपनी दीर्घकालिक उपयोगिता के बारे में अपनी आकांक्षाओं का अनुभव किया है। नई सरकार को अपने मायदनों से सांशोधन करने के लिए विपक्ष और सेवानिवृत्त सेना जनताओं के साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए। इस, इन चुनावों में बड़े झटके को देखते हुए, अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मोदी सरकार अधिक मुसुम सुविधाओं पर विचार कर सकती है जो अव्यवस्था को अस्थिर कर सकती है।

